

## सामान्य समीक्षा

### घटनाक्रमों की समीक्षा

#### (क) वृहद-आर्थिक समीक्षा

वर्ष 2004-05 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अब तक का कार्य निष्पादन वर्ष के आरम्भ में अनुमानित प्रत्याशाओं से कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रक में उछाल द्वारा उत्प्लावित तथा उद्योग एवं सेवाओं में बेहतर निष्पादन से अत्यधिक सहायता पाकर अर्थव्यवस्था ने 2003-04 में 8.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर दर्ज की थी जो 1975-76 तथा 1988-89 को छोड़कर अब तक सर्वोच्च अभिवृद्धि दर है। सामान्यतः न्यून अभिवृद्धि के पश्चात् सशक्त अभिवृद्धि तथा इसके विपर्ययेन प्रत्याशा की जाती है। 2003-04 में 'शानदार' अभिवृद्धि के पश्चात् 2004-05 के लिए आरम्भिक अभिवृद्धि अनुमान 6.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत के बीच केन्द्रित थे। सामान्य प्रत्याशाएं और अधिक कम होकर 6.1 प्रतिशत के आसपास आ गई जब वर्षा जून 2004 में सामान्य होने के पश्चात् बोआई के महत्वपूर्ण जुलाई माह में कम हो गई तथा दक्षिणी-पश्चिमी मानसून में कमी 13 प्रतिशत आकलित हुई। अनुकूल विश्व मुद्रास्फीति माहौल में हास, विशेषरूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं इस्पात में, से अभिवृद्धि एवं मुद्रास्फीति के संबंध में और आशंकाएं उत्पन्न हुईं।

1.2 इस स्थिति में, 7 फरवरी 2005 को जारी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अग्रिम अनुमान के अनुसार, अर्थव्यवस्था में 2004-05 में 6.9 प्रतिशत की अभिवृद्धि होने की संभावना है। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार, आधारित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति 5 फरवरी, 2005 को 5 प्रतिशत थी (सारणी 1.1)। अर्थव्यवस्था ने अल्प दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तेल एवं इस्पात के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा अंतिम किन्तु सब से कम नहीं, सुनामी संबंधी दर्ज किए गए इसके प्रथम अनुभव, जिसने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं पांडीचेरी में

2260 कि.मी. की तटीय रेखा में जीवन एवं सम्पत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है, के बावजूद अर्थव्यवस्था ने अपना अभिवृद्धि संवेग बनाए रखा है।

1.3 वर्ष 2002-03 में 7.0 प्रतिशत की सूखा-प्रेरित गिरावट के पश्चात्, 2003-04 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई। जबकि उद्योग ने 2002-03 में अवलोकित 6.6 प्रतिशत की उच्चतर अभिवृद्धि को कायम रखा, सेवाओं ने अपने निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया जो 2002-03 में 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 9.1 प्रतिशत हो गई। 2003-04 में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रक की अभिवृद्धि व्यापकाधारित थी जिसमें विनिर्माण, जन उपयोगिताओं, व्यापार, होटलों, संवहन तथा संचार समूह एवं सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं ने गत वर्ष की तुलना में उच्चतर अभिवृद्धि दर्ज की।

1.4 वर्ष 2004-05 की शुरूआत उत्प्लावक औद्योगिक वृद्धि, मानसून की शीघ्र शुरूआत तथा एक सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान के साथ एक आशाजनक संकेत से हुई। किन्तु इसी दौरान खरीफ (ग्रीष्म) फसल को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून में कमी, विशेषकर जुलाई में, के कारण क्षति पहुंची। जबकि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में कमी के एक अच्छी रबी फसल की संभाव्यता द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो जाने की संभावना है, 2004-05 में समग्र खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है (चित्र 1.1)। फिर भी खाद्यान्न के पर्याप्त संचित स्टॉकों के कारण खाद्य प्रबंधन पर दबाव न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न-भिन्न कृषि (उदाहरणार्थ सूत, फल तथा सब्जियां, एवं डेयरी) के उत्प्लावक निष्पादन से चालू वर्ष में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रक में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है (सारणी 1.2)। न केवल कृषि में खाद्यान्नों के अंश में गिरावट आई है बल्कि स.घ.उ. में कृषि का अंश भी कम हो गया है, उदाहरणार्थ 2001-02 के बाद से 3.5 प्रतिशत बिंदु तक।

सारणी 1.1 : मुख्य संकेतक

मर्दे	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
<b>सकल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर)</b> (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2065.9	2241.7 पी	2505.7क्यू	2820.1 ए	9.6	8.5 पी	11.8क्यू	12.5 ए
1993-94 की कीमतों पर	1257.6	1310.5 पी	1422.5क्यू	1519.5 ए	6.0	4.2 पी	8.5क्यू	6.8 ए
<b>सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर)</b> (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2081.5	2254.9 पी	2519.8क्यू	2838.1 ए	9.4	8.3 पी	11.7क्यू	12.6 ए
1993-94 की कीमतों पर	1267.9	1318.4 पी	1430.5क्यू	1529.4 ए	5.8	4.0 पी	8.5क्यू	6.9 ए
<b>कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक</b> (हजार करोड़ रुपए)								
(1993-94 की कीमतों पर)	304.7	283.4 पी	310.6क्यू	313.9 ए	6.3	-7.0 पी	9.6क्यू	1.1 ए
<b>कृषि उत्पादन का सूचकांक (1)</b>								
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	178.8	154.1	180.1 पी	179.2 पी	7.9	-13.8	16.9 पी	-0.5 पी
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	212.9	179.4	212.4 पी	206.4 पी	8.1	-15.7	18.4 पी	-2.8 पी
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	167.0	176.6	189.0	199.4 ^	2.7	5.8	7.0	8.4 ^
<b>उत्पन्न बिजली</b> (बिलियन के.डब्ल्यू.एच. में)								
थोक मूल्य सूचकांक (3)	515.3	531.6	558.3	437.9 ^	3.1	3.2	5.0	6.5 ^
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (4)	161.8	172.3	180.3	188.6 #	1.6	6.5	4.6	5.0 #
मुद्रा आपूर्ति (एम 3)(5) (हजार करोड़ रुपए)	468	487	504	521 \$	5.2	4.1	3.5	3.8 \$
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	1,498.4	1718.0	2003.1	2193.3(6)	14.1	14.7	16.6	13.9(6)
(मिलियन अमरीकी डालर)	2,45,200	2,97,206	3,59,108	3,76,815***	6.2	21.2	20.8	32.1***
वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रुपए)	51,413	61,412	78,149	83,442***	1.7	19.4	27.3	34.7***
(मिलियन अमरीकी डालर)	2,09,018	2,55,137	2,93,367	2,74,313***	2.7	22.1	15.0	23.1***
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (7)	43,827	52,719	63,843	60,754***	-1.6	20.3	21.1	25.6***
(करोड़ रुपए)	2,49,118	3,41,476	4,66,215	540246 *	35.0	37.1	36.5	18.3 *
(मिलियन अमरीकी डालर)	510,49	71,890	1,07,448	123654 *	29.1	40.8	49.5	22.7 *
विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर) (8)	47.69	48.40	45.95	45.18 @	-4.2	-1.5	5.3	2.1 @

टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (नई शृंखला आधार वर्ष 1993-94)

क्यू-त्वरित अनुमान ए-अग्रिम अनुमान पी-अनन्तिम @ अप्रैल-जनवरी 2004-05 के लिए औसत विनिमयदर

\* जनवरी 2005 के अंत में \*\* दिसम्बर 2004 के अंत में \*\*\* अप्रैल-जनवरी 2004-05,

# 5 फरवरी, 2005 के अनुसार # दिसम्बर, 2004 के अनुसार + द्वितीय अग्रिम अनुमान 2004-05

^ अप्रैल-दिसम्बर, 2004

1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त त्रय वर्ष = 100 (संशोधित)

2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार 1993-94 = 100)

3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)

4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982 = 100)

5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।

6. 21 जनवरी, 2005 को वर्षानुवर्ष वृद्धि (11 अक्टूबर, 2004 से एक गैर बैंकिंग कम्पनी के बैंकिंग कम्पनी में रूपांतरण को घटाकर)।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।

8. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मूल्यवर्धन दर (+)/ह्रास (-) को निर्दिष्ट करता है।

सारणी 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक वास्तविक वृद्धि दरें (उपादान लागत पर)								
संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन							
	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (पी)	2003-2004 (क्यू.)	2004-2005 (ए)
I. कृषि एवं संबद्ध उद्योग	-2.4	6.2	0.3	-0.1	6.3	-7.0	9.6	1.1
II. उद्योग	4.3	3.7	4.8	6.5	3.6	6.6	6.6	7.8
खनन तथा उत्खनन	9.8	2.8	3.3	2.4	2.5	9.0	6.4	5.3
विनिर्माण	1.5	2.7	4.0	7.4	3.6	6.5	6.9	8.9
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	7.9	7.0	5.2	4.3	3.7	3.1	3.7	6.3
निर्माण	10.2	6.2	8.0	6.7	4.0	7.3	7.0	5.7
III. सेवाएं	9.8	8.4	10.1	5.5	6.8	7.9	9.1	8.9
व्यापार, होटल, संवहन तथा संचार	7.8	7.7	8.5	6.8	9.0	9.8	11.8	11.3
वित्तीय सेवाएं	11.6	7.4	10.6	3.5	4.5	8.7	7.1	7.1
सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	11.7	10.4	12.2	5.2	5.1	3.9	5.8	6.0
IV. उपादान लागत पर कुल स.घ.उ.	4.8	6.5	6.1	4.4	5.8	4.0	8.5	6.9
पी : अनन्तितम                      क्यू : त्वरित अनुमान;                      ए : अग्रिम अनुमान स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।								

1.5 खरीफ फसल में इस धक्के के बावजूद, 2003-04 में प्रेक्षित समग्र अभिवृद्धि संवेग के चालू वर्ष में जारी रहने के कारण 2004-05 के लिए दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है। वैश्विक सुधार जारी रहने के स्पष्ट संकेतों और विश्व उत्पादन अभिवृद्धि के वर्ष 2004 में 5.0 प्रतिशत होने के अनुमान से, जो लगभग तीन दशकों में उच्चतम है, भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन 2004-05 में संतोषजनक होने की आशा है।

1.6 स.घ.उ. में चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में 7.4 प्रतिशत की तथा दूसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की सादृश तिमाहियों में हुई 5.3 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत की वृद्धियों की तुलना में है। दूसरी तिमाही में वृद्धि में ह्रास कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रक में 0.8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि, सेवा क्षेत्रक में प्रथम तिमाही में 9.5 प्रतिशत की तुलना में 8.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि तथा सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं की अभिवृद्धि में गिरावट के कारण है। उद्योग में अभिवृद्धि प्रथम तिमाही में 6.9 प्रतिशत से त्वरित होकर दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत हो गई। उद्योग के भीतर, विनिर्माण में अभिवृद्धि प्रथम तिमाही में 8.0 प्रतिशत से त्वरित होकर द्वितीय तिमाही में 9.3 प्रतिशत हो गई जो 1997-98, जब से सी एस ओ ने त्रैमासिक अनुमान संकलित करने आरम्भ किए हैं, के बाद से किसी भी तिमाही में हुई उच्चतम वृद्धि है। द्वितीय तिमाही में अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष के प्रथमार्ध में 7.0 प्रतिशत

पर समग्र अभिवृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हासिल की गई 6.9 प्रतिशत की अभिवृद्धि से मामूली रूप से अधिक थी।

1.7 वर्ष 2004-05 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में एक आकस्मिक उछाल आया जिसका कारण अनेक कारकों का संयोजन था जिनमें से कुछ बहिर्जात थे यथा पेट्रोलियम की वैश्विक कीमतों में तीव्र वृद्धि, अल्प वर्षा प्रेरित मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों के संचयनों में से मौद्रिक निकासी। वर्ष 2004-05 में 3 अप्रैल 2004 को 4.5 प्रतिशत की एक बिन्दु दर बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर से आरम्भ हो कर 28 अगस्त, 2004 को 8.7 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति का चरम स्तर परिलक्षित हुआ जो विगत चार वर्षों में सर्वाधिक था। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा किए गए त्वरित मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों के साथ-साथ पेट्रोलियम की वैश्विक कीमतों में थोड़ी सी कमी आने से मुद्रास्फीति में अधोगामी रुझान आया तथा 5 फरवरी, 2005 को यह एक वर्ष पूर्व के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 5 प्रतिशत थी।

1.8 तथापि 5 फरवरी, 2005 को 6.4 प्रतिशत की 52-सप्ताह औसत मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष दर्ज 5.5 प्रतिशत की तुलना में उच्च थी। चालू वर्ष में 5 फरवरी, 2005 तक विनिर्मित उत्पादों तथा प्राथमिक वस्तुओं, दोनों में क्रमशः 4.5 प्रतिशत तथा 1.6 प्रतिशत पर निम्नतर वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दर्ज हुई जो पिछले वर्ष दर्ज किए गए क्रमशः

6.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत की तुलना में है। किन्तु तेल एवं खनिजों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने के कारण ईंधन, विद्युत, बिजली तथा स्नेहन समूह की मुद्रास्फीति में त्वरण था जो पिछले वर्ष के 7.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 10.0 प्रतिशत हो गई। 5 फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार उच्च वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति परिलक्षित करने वाले मुख्य समूहों में खनिज (135.5 प्रतिशत), कोयला (16.2 प्रतिशत), पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहन (पीओएल) (14.6 प्रतिशत), शर्करा समूह (21.4 प्रतिशत) तथा बुनियादी धातु एवं उत्पाद (16.0 प्रतिशत) शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक में 21.5 प्रतिशत के भार के साथ वर्तमान मुद्रास्फीति में इन मदों का योगदान विगत वर्ष के 52 प्रतिशत की तुलना में 88 प्रतिशत था। वैश्विक मांग में उछाल के कारण इन वस्तुओं (चीनी को छोड़कर) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि दर्शाती है कि मुद्रास्फीति का एक प्रमुख भाग बाह्य कारकों के कारण है।

1.9 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा यथामापित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति अप्रैल, 2003 में 5.1 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घटकर मार्च 2004 में 3.5 प्रतिशत हो गई एवं अप्रैल 2004 में और घटकर 2.2 प्रतिशत हो गई। तत्पश्चात् सी पी आई मुद्रास्फीति दर एक वृद्धिकारी रूझान दर्ज करते हुए सितंबर, 2004 में 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, क्योंकि डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति ने भी उपभोक्ता मूल्यों को और बढ़ाया। नीतिगत उपायों के अंशतः प्रत्युत्तर में और तेल आयातों के बाहरी दबाव के तदनन्तर कम होने से, अक्टूबर, 2004 में सी पी आई घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया तथा दिसंबर, 2004 में और घटकर 3.8 प्रतिशत हो गया। सी पी आई मुद्रास्फीति भी, जिसे सामान्य मुद्रास्फीति का एक अधिक उपयुक्त संकेतक समझा जाता है, दिसंबर 2004 में 6.7 प्रतिशत की औसत डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति से काफी निम्नतर है।

1.10 डब्ल्यू पी आई की तुलना में सी पी आई द्वारा प्रदर्शित निम्नतर मुद्रास्फीति मुख्यतः वस्तुओं के खाद्य समूह के कारण थी जिनमें मुद्रास्फीति समग्र मुद्रास्फीति से निम्नतर थी और डब्ल्यू पी आई के सापेक्ष सी पी आई में उनका भार उच्चतर था। डब्ल्यू पी आई में 17.63 प्रतिशत के भार के साथ घरों के लिए तीस अत्यावश्यक वस्तुओं ने एक वर्ष पूर्व दर्ज 4.9 प्रतिशत की तुलना में 5 फरवरी, 2005 को 4.5 प्रतिशत की 12-मासी बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर्ज की और ये एक वर्ष के 14.0 प्रतिशत की तुलना में समग्र

मुद्रास्फीति के 15.6 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थी। 30 मदों में से, 11 मदों ने पिछले वर्ष की तुलना में सम्पूर्ण मूल्यों में गिरावट दर्ज की, जबकि दिनांक 5 फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार 8 मदों के लिए वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत से कम थी। आलू, चाय, शर्करा, नमक, बाजरा, गुड़ और कोकिंग कोयले ने द्विअंकी मुद्रास्फीति दर्शायी जो अंशतः शर्करा, गुड़ और कोकिंग कोयले को छोड़कर, इन मदों के संपूर्ण मूल्यों में पिछले वर्ष में परिकल्पित गिरावट के कारण थी। इसके अतिरिक्त, खाद्य समूह मुद्रास्फीति, डब्ल्यू पी आई की अपेक्षा सी पी आई में निम्नतर थी, जो यह सुझाती है कि खाद्य मूल्य खुदरा बाजारों की तुलना में थोक बाजारों में अधिक तेजी से बढ़े।

1.11 वर्ष 2004-05 की दूसरी तिमाही में सरकार ने चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों, उत्पाद एवं सीमाशुल्क को कम करके, अमिश्र इस्पात पर सीमाशुल्कों को कम करके; लोहे एवं इस्पात के गलने वाले स्क्रैप को सीमाशुल्क से छूट प्रदान करके; तथा अनेक वनस्पति तेलों के प्रशुल्क मूल्य घटा कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में नकदी निकासी को नियंत्रित करने के लिए नकद प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) में 18 सितम्बर 2004 एवं 2 अक्टूबर 2004 को और 27 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी प्रतिवर्ती-रिपो दर में वृद्धि की। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तदनुसार गिरावट सहित इन उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता की।

1.12 पिछले दो वित्तीय वर्षों में, संयुक्त राज्य (यू.एस) में राजकोषीय और चालू लेखा घाटों के बढ़ने से, रुपया, अमरीकी डालर की तुलना में सुदृढ़ हो रहा था। मई-अगस्त 2004 के दौरान इस रूझान में एक संक्षिप्त समय के लिए प्रतिवर्तन परिलक्षित हुआ। अन्य प्रमुख परिवर्तनीय मुद्राओं के रूप से अधिक सुदृढ़ होने के कारण (अमरीकी डालर की तुलना में) रुपया प्रमुख डालर-भिन्न मुद्राओं की तुलना में कमजोर हो गया। उच्चतर अमरीकी ब्याज दरों की बढ़ती हुई प्रत्याशाओं और उत्प्लावक वृद्धि ने अमरीकी डालर के वर्धन को संतुलित करने में योगदान दिया। इसके कारण मई 2004 से डालर की तुलना में रुपए का मूल्यहास शुरू हुआ। अप्रैल 2004 के पश्चात्, अगस्त, 2004 तक रुपया अन्य सभी मुख्य डालर-भिन्न वैश्विक मुद्राओं (यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा येन) की तुलना में ह्रासित हो गया। मई-जुलाई, 2004 में निवल पोर्टफोलियो बहिर्वाह भी परिलक्षित हुए।

1.13 रुपए की विनिमय दर ने 2004-05 में बाजार दशाओं के अनुक्रियास्वरूप अनुचित नम्यता प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में भी विनिमय की प्रति-मुद्रा दरों में भारी परिवर्तन परिलक्षित हुए। अतः विशेषतया पूंजीगत अंतर्वाहों के पुनः शुरू होने के साथ अमरीकी डालर और अन्य डालर-भिन्न मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए का ह्रासित रूझान क्रमशः सितंबर और अगस्त, 2004 से प्रतिवर्तित हो गया। यूरो के अमरीकी डालर की तुलना में तीव्रता से सुदृढ़ होने से अक्टूबर, 2004 से रुपया सभी मुख्य डालर-भिन्न मुद्राओं की तुलना में पुनः कमजोर होना शुरू हो गया। जनवरी, 2005 में सांकेतिक अर्थों में रुपए का मूल्य सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में बढ़ गया।

1.14 वास्तविक प्रभावी अर्थों में जून, अगस्त और सितंबर, 2004 में रुपए की कीमत बढ़ी। मुख्यतः विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के नवीकृत अंतर्वाहों और वैश्विक मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के कमजोर होने के कारण सितंबर, 2004 से अमरीकी डालर की तुलना में मामूली रूप से सुदृढ़ होने के बावजूद, घरेलू मुद्रास्फीति में कमी और डालर-भिन्न मुद्राओं की तुलना में तीव्र गिरावट के कारण, वास्तविक प्रभावी अर्थों में रुपया मूल्य ह्रासित होना शुरू हुआ। यह रूझान 2004 के अंत तक जारी रहा।

1.15 भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में यह बढ़ता हुआ रूझान जारी रहा जिससे ऐसे प्रारक्षित भंडार (जिसमें सोना, एस डी आर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित राशि शामिल है) 4 फरवरी, 2005 को 128.91 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित स्तर पर पहुंचकर भारत के 114 बिलियन अमरीकी डालर सितंबर-अंत, 2004 के विदेशी ऋण से अधिक हो गए। तथापि, इस वर्ष अब तक प्रारक्षित राशि में 15.9 बिलियन अमरीकी डालर की अभिवृद्धि, पिछले वर्ष की सादृश अवधि के दौरान 31 बिलियन से अधिक अमरीकी डालर और संपूर्ण वर्ष 2003-04 में 36.9 बिलियन अमरीकी डालर की अभूतपूर्व वृद्धि की तुलना में कम है। प्रारक्षित भंडारों की वृद्धि में धीमापन जो पूर्णतः निराशाजनक विकास नहीं है, तीन मुख्य कारणों से है। पहला, पिछले वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान अधिशेष की तुलना में वर्ष की सादृश अवधि के दौरान एक चालू लेखा घाटे का आविर्भाव। दूसरा, ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दरों के समायोजन से अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां कम हो गईं। तीसरा, वर्ष 2003-04 के सापेक्षतया, जब अमरीकी डालर के कमजोर होने के

कारण वृहद-मूल्यांकन लाभ थे, चालू वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

1.16 वर्तमान लेखा शेष तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निरंतर अधिशेष में रहने के पश्चात्, चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध (अप्रैल-सितंबर 2004-05) में घाटे में परिवर्तित हो गया। चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में चालू लेखे में अधिशेष न केवल प्रतिवर्तित हो गया, किन्तु दूसरी तिमाही में घाटे से प्रतिसंतुलित भी हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 के प्रथमार्द्ध में 3.2 बिलियन अमरीकी डालर का समग्र चालू लेखा घाटा हुआ। वर्तमान लेखा विकास का श्रेय दो मुख्य कारणों को दिया जा सकता है। पहला, उच्च मूल्यों के कारण न केवल पी ओ एल आयात बिल में बल्कि 'सर्वाफा-भिन्न' पी ओ एल-भिन्न आयातों में भी वृद्धि होने से, जिससे अमरीकी डालर अर्थों में निर्यातों में वृद्धि 23 प्रतिशत से अधिक पर पहुंच गई, एक विशाल व्यापार घाटा उत्पन्न हुआ। दूसरा, चालू वर्ष के पूर्वार्ध में निवल अदृश्य अधिशेष में 23 प्रतिशत की सापेक्ष संतुलित वृद्धि हुई जो विगत वर्ष की सादृश अवधि में 35 प्रतिशत की तुलना में थी। जहां श्रमिकों के प्रेषणों में सीमान्तिक रूप से गिरावट आई, निवल कारक-भिन्न सेवाओं में 174 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष मजबूत वृद्धि दर्ज की गई तथा सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 28.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2004-05 के प्रथमार्द्ध में उत्प्लावक बने रहे। चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों में विदेशी माल व्यापार खाते में गतिविधियां तीन उभरते हुए रूझानों की द्योतक हैं।

1.17 पहला विगत दो वर्षों में प्रत्येक में 20 प्रतिशत से अधिक की सतत् वृद्धि के पश्चात् अमरीकी डालर के अर्थ में माल निर्यात वृद्धि (25.6 प्रतिशत) की उत्प्लावकता, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के पुनरुज्जीवन और वृद्धित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ निर्यातों की मात्रा में सतत् वृद्धि प्रतिबिंबित करती है। वस्तु वार निर्यात वृद्धि व्यापकाधारित बनी रही जिसमें विनिर्माण क्षेत्र सब से आगे था। इस उच्च वृद्धि के मुख्य चालक अभियांत्रिकी वस्तुएं, रत्न और आभूषण, वस्त्र, रसायन और संबद्ध उत्पादों तथा पेट्रोलियम उत्पादों के पांच प्रमुख क्षेत्रक थे। तथापि, निर्यातों की उत्प्लावकता के बावजूद, विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों के बीच, भारत का स्थान पिछले वर्ष के 30वें से कम होकर 2003 में 31वां हो गया। विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा दोगुना कर 1.5 प्रतिशत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2008-09 तक निर्यातों के लिए 150 बिलियन अमरीकी डालर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

1.18 दूसरे, पी ओ एल-भिन्न, सर्राफा-भिन्न माल के आयातों में, अप्रैल-जनवरी, 2004-05 में 33.7 प्रतिशत की अनुमानित सशक्त वृद्धि, निवेश सहित उत्प्लावक घरेलू मांग, वास्तविक अर्थों में रूप में हल्की सुदृढ़ता और अधिक आयात उदारीकरण प्रतिबिंबित करती है।

1.19 तीसरे, भारत के प्रबल व्यापारी भागीदारों के रूप में आसियान + 3 (चीन, जापान और कोरिया) देशों का उद्गमन, जो वर्ष 2003-04 में भारत के कुल माल व्यापार के 19.9 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थे जिनके पश्चात् क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत के हिस्सों के साथ ई.यू. और उत्तरी अमरीका का स्थान आता है, व्यापार-क्षितिजों के व्यापकीकरण और 'पूर्व-देखो' दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। अपने व्यापार क्षितिजों को और व्यापक बनाने के लिए डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी के अलावा, भारत ने स्वयं को अनेक द्विपक्षीय करारों में भी शामिल किया।

1.20 अप्रैल-सितंबर, 2004 में पूंजीगत लेखे अधिशेष भी अप्रैल-सितंबर, 2003 में 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से निम्नतर थे। वाणिज्यिक उधारों के अत्यधिक अंतर्वाहों के साथ-साथ उत्प्लावक विदेशी निवेश अंतर्वाहों ने पूंजीगत लेखे को बनाए रखा। वर्ष 2004-05 के प्रथमार्द्ध में भुगतान संतुलन अधिशेष लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर था, जो अप्रैल-सितंबर 2003 से लगभग आधा था।

1.21 वर्ष 2003-04 में, पूंजीगत लेखा अधिशेष दोगुना होकर 20 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया। मुख्यतः भारतीय स्टॉक बाजारों में अत्यधिक तेज़ी के मनोभावों द्वारा चालित पोर्टफोलियो विविधता के कारण, निवल विदेशी निवेश अंतर्वाहों में 255 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 में पिछले वर्ष की 3.0 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में अनिवासी भारतीय जमाराशियों में 3.6 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध के दौरान पूंजीगत लेखा अधिशेष में रहा परन्तु अप्रैल-सितंबर, 2003 की तुलना में कम स्तर पर, जिससे पोर्टफोलियो और बैंकिंग के पूंजीगत अंतर्वाहों में तीव्र गिरावट प्रतिबिंबित होती है। पिछले वर्ष की सादृश अवधि की तुलना में पोर्टफोलियो अंतर्वाह लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर गिरकर 512 मिलियन अमरीकी डालर हो गए। अनिवासी भारतीय जमाराशियों, जो बैंकिंग पूंजी की एक प्रबल घटक हैं-की ब्याज दरों पर प्रीमियम में गिरावट के कारण इनमें पिछले वर्ष की सादृश अवधि में वृद्धित 2.2 बिलियन अमरीकी डालर

की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2004 में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई। एक अधिक उदारीकृत व्यवस्था और देश के विदेशी मुद्रा दर निर्धारण में सुधार के साथ, पिछले वर्ष की सादृश अवधि की तुलना में वर्ष 2004-05 के प्रथमार्द्ध में विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) में लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर की विशाल वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि पोर्टफोलियो अंतर्वाहों और बैंकिंग पूंजी में गिरावट को प्रतिसंतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

1.22 चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में निवल पोर्टफोलियो अंतर्वाहों में गिरावट, प्रथम तिमाही में विशेष रूप से प्रबल थी जब मध्य 2004 में भारतीय स्टॉक बाजार में चंचलता थी तथा अमरीकी ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जोखिम-प्रतिलाभ भुगतानों के पुनर्मूल्यांकन किए गए। हाल ही के आंकड़े निर्दिष्ट करते हैं कि जुलाई 2004 से भारतीय स्टॉक बाजार में तेज़ी के रूझानों की बहाली से, पोर्टफोलियो अंतर्वाहों में तीव्रता आई है। इसी प्रकार, नवंबर, 2004 से अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमाओं में ऊर्ध्वमुखी संशोधनों ने ऐसी जमाराशियों में प्रथमार्द्ध में गिरते रूझानों को प्रतिवर्तित करने में योगदान दिया है।

1.23 भारत की विदेशी ऋण स्थिति में सुधार वर्ष 2003-04 में भी जारी रहा। अपनी वर्तमान विवेकपूर्ण विदेशी ऋण नीति को जारी रखने के अलावा, कुछ पहलों जैसे मंहगे विदेशी ऋण का समय से पूर्व भुगतान और ब्याज दरों के साथ-साथ अनिवासी भारतीय जमाराशियों की संरचना का यौक्तिकीकरण, ने वर्ष 2003-04 के दौरान ऋण-निर्वहनीयता संकेतकों के सुधार में योगदान किया। उदाहरणार्थ, स.घ.उ. के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण मार्चात 2003 को 20.2 प्रतिशत से गिरकर मार्चात 2004 तक 17.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, कुल विदेशी ऋण में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मार्चात 2003 में 4.8 प्रतिशत से गिरकर मार्चात 2004 में 4.3 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में, विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर, और कानूनी कारणों से जैसे विस्तृत आयात मांग को प्रतिबिंबित करने वाले अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट में वृद्धि, जैसे संकेतकों ने सीमान्तिक हास दर्शाया है।

1.24 वर्ष के शुरू में इसके भंडार की तुलना में प्रारक्षित निधि में अभिवृद्धि जो 2002-03 में 9.2 प्रतिशत से त्वरित होकर 2003-04 में 18.3 प्रतिशत की उच्च सीमा तक पहुंच गई थी, चालू वर्ष में 28 जनवरी, 2005 तक गिरकर 6.4 प्रतिशत पर आ गई। प्रारक्षित निधि में तदनुरूपी अभिवृद्धि

एक वर्ष पहले 7.8 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में प्रारक्षित निधि की न्यून अभिवृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों (एन एफ ए) में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 32.8 प्रतिशत की तुलना में 15.9 प्रतिशत की न्यून अभिवृद्धि के कारण थी। वर्ष 2003-04 (पूरे वर्ष में 62.8 प्रतिशत) में परिलक्षित सरकार के निवल आर बी आई क्रेडिट में तीव्र गिरावट चालू वर्ष में जारी रही और 28 जनवरी, 2005 तक और गिरकर 69.9 प्रतिशत हो गई तथा इस के परिणामस्वरूप उस तारीख में एन एफ ए प्रारक्षित निधि का संघटन 120.9 प्रतिशत था। चालू वर्ष में प्रारक्षित निधि की न्यून अभिवृद्धि के बावजूद नकदी प्रबंधन प्रमुख चिंता बनी रही। यह पिछले वर्ष प्रारक्षित निधि में तीव्र वृद्धि के पश्चात् नकदी समंजन सुविधा के अंतर्गत बकाया प्रतिवर्ती रिपो के रूप में 81,000 करोड़ रुपए से अधिक नकदी निकासी, सरकारी आधिक्य शेष और पिछले वर्ष से बैंकों की अतिरिक्त प्रारक्षित निधि के कारण था। इस निकासी ने नकदी प्रबंधन में एक नई समस्या खड़ी कर दी। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की आरंभिक सीमा को पार करने के पश्चात् 26 अगस्त, 2004 को एम एस एस के अंतर्गत सीमा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में एक ही रात के निर्धारित रिपो के साथ 7 दिवसीय और 14 दिवसीय प्रतिवर्ती रिपो की नीलामी बंद करना और नकदी प्रारक्षित अनुपात से 50 आधार बिंदु बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना शामिल हैं।

1.25 वर्ष के शुरू के भंडार की तुलना में स्थूल धन राशि (एम3) पूरे पिछले वर्ष में 16.6 प्रतिशत के ऊंचे स्तर और उससे पिछले वर्ष की उसी अवधि में 12.1 प्रतिशत की तुलना में 21 जनवरी, 2005 तक चालू वर्ष में 9.5 प्रतिशत (रूपान्तरण का निवल) बढ़ी। धनराशि गुणक-प्रारक्षित निधि के प्रति एम3 का अनुपात- जो मार्चात 2002 में 4.43 से बढ़कर मार्चात 2003 में 4.65 हो गया था, मार्चात 2004 में गिरकर 4.59 हो गया। दिनांक 21 जनवरी, 2005 को यह अनुपात 4.72 पर था।

1.26 चालू वर्ष में धनापूर्ति की न्यून अभिवृद्धि के बावजूद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक उधार में प्रभावशाली अभिवृद्धि हुई थी। रूपान्तरण को घटाकर सकल बैंक उधार पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 9.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 21 जनवरी, 2005 तक 19.9 प्रतिशत हो गए। खाद्य और खाद्य-भिन्न दोनों उधारों में अभिवृद्धि देखी गई थी जो उत्तरवर्ती के मामले में अधिक थी। खाद्य उधार पिछले वर्ष की 25.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में चालू

वर्ष में 21 जनवरी, 2005 तक 15.2 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि खाद्य-भिन्न उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11.9 प्रतिशत की तुलना में प्रभावशाली रूप से 20.1 प्रतिशत बढ़े जो 1996-97 से दर्ज की गई सबसे अधिक अभिवृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए अग्रिम 2003-04 में निवल बैंक उधार के 40 प्रतिशत का लक्ष्य पार करते हुए 44.0 प्रतिशत पर पहुंच गए। तथापि, कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रही है।

1.27 सरकार ने चालू वर्ष में कृषि उधार में 30 प्रतिशत वृद्धि और तीन वर्षों में इस क्षेत्रक में उधार प्रवाह को दोगुना करने की परिकल्पना करते हुए एक सुस्पष्ट व्यापक नीति घोषित की है।

1.28 वर्ष 2003-04 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ था। जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में निवल लाभों का अनुपात 2002-03 में 1.0 प्रतिशत से मामूली रूप से सुधरकर 2003-04 में 1.1 प्रतिशत हो गया, कुल आस्तियों में प्रचालनात्मक लाभों का अनुपात उसी अवधि में 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 2.7 प्रतिशत हो गया। एस सी बी की लाभप्रदता ने चालू वर्ष के प्रथमार्ध से राजकोषीय आय में गिरावट के कारण ह्रासकारी प्रवृत्ति दर्शायी है। कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ का वार्षिकीकृत अनुपात 2004-05 के प्रथमार्ध में 1.1 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.3 प्रतिशत की तुलना में है। एस सी बी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन पी ए) में महत्वपूर्ण गिरावट हुई थी। एस सी बी की सकल एन पी ए कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में 2002-03 में 4.0 प्रतिशत से गिरकर 2003-04 में 3.3 प्रतिशत हो गई। निवल एन पी ए के तदनुसूची अनुपात में गिरावट 1.9 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत थी। एस सी बी का जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात 2002-03 में 12.7 प्रतिशत से सुधरकर 2003-04 में 12.9 प्रतिशत हो गया।

1.29 चालू वर्ष में पांच प्रमुख बैंकों की जमा दरों में 25 आधार बिंदु की मामूली वृद्धि हुई। आवास ऋणों की ब्याज दरों में भी मामूली दृढ़ता देखी गई। मांग मुद्रा दरें वर्ष के उत्तरार्ध में बढ़ गईं जो बैंक उधार की अपेक्षतया उच्च अभिवृद्धि प्रतिबिंबित करती हैं। फिर भी ब्याज दरें सामान्य बनी रहीं। पांच प्रमुख बैंकों की आरम्भिक मुख्य उधार दरें पिछले वर्ष में प्रचलित दरों की तुलना में दिसंबर, 2004 में 25 से 50 आधार बिंदु नीचे थी।

1.30 राजकोषीय सुदृढीकरण ने नब्बे के दशक के आरंभ में आशाजनक शुरूआत के पश्चात् 1997-98 से लड़खड़ाना शुरू कर दिया। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो 1990-91 में 6.6 प्रतिशत से गिरने के पश्चात् 1996-97 में 4.1 प्रतिशत हो गया था, प्रत्येक वर्ष बढ़ता हुआ 2001-02 में 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। राजकोषीय सुदृढीकरण में प्रगति 2002-03 में पुनः शुरू हुई। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2003-04 में 4.6 प्रतिशत का अनुपात 5.6 प्रतिशत के बजट अनुमान से निम्नतर था। वर्ष 2004-05 में इस अनुपात के और सुधर कर 4.4 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी।

1.31 वर्ष 1996-97 तक राजकोषीय घाटे में इसी तरह की प्रवृत्ति परिलक्षित करने के पश्चात् राजस्व घाटे में ह्रास तदन्तर वर्षों में कहीं अधिक तीव्र था। राजस्व घाटे में वृद्धि 2001-02 तक जारी रही जब यह स.घ.उ. के 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। राजस्व घाटा 2003-04 (अनंतिम) में गिरकर स.घ.उ. का 3.6 प्रतिशत हो गया परन्तु इस स्तर पर भी यह 1990-91 के सुधार-पूर्व वर्ष में अवलोकित स.घ.उ. के 3.3 प्रतिशत के स्तर से अधिक था। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का बढ़ता हुआ हिस्सा राजकोषीय घाटे की संरचना और व्यय की गुणवत्ता में सुस्पष्ट रूप से ह्रास दिखलाता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का हिस्सा 1990-91 में 49.4 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 78.0 प्रतिशत हो गया जिसे बजट अनुमान में स.घ.उ. के 2.5 प्रतिशत के न्यूनतर राजस्व घाटे का लक्ष्य रखते हुए 2004-05 में प्रतिवर्तित किया जाना था।

1.32 चालू वर्ष 2004-05 पहला वर्ष है जब राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2003 लागू है। जुलाई, 2004 में नियमों की अधिसूचना के साथ केन्द्रीय वित्त साधन एफ आर बी एम अधिनियम के अनुशासन के अध्यक्षीन हैं। तदनुसार, सरकार ने राजस्व व राजकोषीय घाटों में निर्धारित न्यूनतम कटौतियों से आगे जाते हुए 2004-05 के बजट में अग्रवर्ती राजकोषीय समंजन का लक्ष्य रखा है। स.घ.उ. के अनुपातों के रूप में राजकोषीय और राजस्व घाटों में बजटीय कटौतियां एफ आर बी एम नियमों के अंतर्गत अधिदेशित क्रमशः 0.3 और 0.5 प्रतिशत अंक की न्यूनतम कटौती की तुलना में संशोधित अनुमान से क्रमशः 0.4 और 0.9 प्रतिशत अंक अधिक है।

1.33 चालू वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान केंद्रीय वित्तों का कार्यनिष्पादन बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में, राजकोषीय और राजस्व घाटे क्रमशः

65.7 और 82.7 प्रतिशत थे जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में अवलोकित क्रमशः 60.2 प्रतिशत और 65.0 प्रतिशत से अधिक थे। कर बकाया के संग्रहण का जोरदार अभियान, सरकारी इक्विटी पर न्यूनतम लाभांश भुगतान का संग्रहण, आयोजना-भिन्न और वेतन-भिन्न व्यय के अंतर्गत बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत कटौती और वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमान के 33 प्रतिशत से अनधिक पर प्रतिबंधित करने से 2004-05 की अंतिम तिमाही में केंद्रीय वित्तों में सुधरा हुआ कार्य-निष्पादन होना प्रत्याशित है।

1.34 राज्यों की राजकोषीय स्थिति सुधारने के प्रयास जारी हैं। केंद्र और राज्यों के समेकित राजस्व घाटे को 2003-04 (सं. अ.) में स.घ.उ. के 9.4 प्रतिशत से नीचे लाकर 2004-05 में स.घ.उ. का 7.9 प्रतिशत करने की बजटीय व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए 1990-91 और 2003-04 (सं.अ.) के बीच स.घ. उ. के अनुपात के रूप में राजस्व और राजकोषीय घाटे क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत हो गए थे। वर्ष 2004-05 में राजस्व और राजकोषीय घाटे को क्रमशः स.घ.उ. के 1.4 प्रतिशत और स.घ.उ. के 3.6 प्रतिशत तक नीचे लाने की बजटीय व्यवस्था की गई है। केन्द्र राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऋण अदला बदली योजना के तहत राज्यों ने चालू वर्ष में दिसम्बर 2004 तक केंद्र से लिए 34,085 करोड़ रुपए के उच्च लागत वाले उधारों की अतिरिक्त बाजार उधारों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) से ऋण लेकर अदला-बदली की है। राज्यों द्वारा अदला-बदली किए गए संचयी उच्च लागत ऋणों की राशि दिसंबर अंत, 2004 में 92,444 करोड़ रुपए बैठती है। राज्यों का 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू करने का निर्णय उन प्रयासों की पराकाष्ठा दर्शाता है जो घरेलू व्यापार करों में सुधार करने के लिए एक दशक से भी पहले शुरू किए गए थे।

1.35 वर्ष 2005-06 में लागू होने वाली बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सुधारों की मार्ग रूपरेखा जिन का आशय बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रकटित निर्वहनीय मार्ग पर राज्यों के वित्तों को लाना है, में साझेदारी योग्य केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत करना और राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन के अध्यक्षीन 31 मार्च, 2005 को बकाया और मार्च 2004 तक अनुबंधित केंद्रीय ऋणों का



समेकन (1,28,795 करोड़ रुपए) और 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि के लिए उसका पुनर्निर्धारण शामिल है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उधारों व गारंटियों को कम करने के मार्ग पर आधारित राजकोषीय घाटा कम करने के दृष्टिगत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। आयोग ने राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने से जुड़ी ऋण-माफी योजना की अनुशंसा भी की है।

1.36 इक्विटी बाजारों में 2003-04 व चालू वर्ष में अब तक उछाल जारी रहा है। शीर्ष के 50 स्टॉकों (निफ्टी) ने 2003 में 72 प्रतिशत लाभ के बाद 2004 में 11 प्रतिशत लाभ का सृजन किया। लघु स्टॉकों (निफ्टी जूनियर) के दूसरे समूह ने 2003 में 141 प्रतिशत लाभ के बाद 2004 में 31 प्रतिशत लाभ का सृजन किया। ये सुदृढ़ लाभ अधिकांशतः निगमों के लाभों में अभिवृद्धि प्रतिबिंबित करते हैं, प्रत्याशाओं में परिवर्तन नहीं। कलेंडर वर्ष 2003 में सुदृढ़ इक्विटी सूचकांक लाभ ने 2004 में प्राथमिक बाजार के पुनरुज्जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। समग्र रूप से सार्वजनिक निर्गम मोटे तौर पर पांच गुणा बढ़कर 2004 में 35,859 करोड़ रुपए हो गए। यह अभिवृद्धि इक्विटी निर्गमों और विशेषतया इक्विटी आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों में केंद्रित थी।

1.37 कुल बिक्री के अर्थों में भारत में प्रतिभूति बाजार सुदृढ़ रूप से विकसित हुआ है। 2004 में इक्विटी स्पाट और व्युत्पाद बाजारों व सरकारी बांडों के लिए तत्स्थानिक बाजार में कुल कारोबार क्रमशः 43 लाख करोड़ रुपए और 11 लाख करोड़ रुपए हुआ। वस्तु फ्यूचर्स में कुल कारोबार अप्रैल-सितंबर, 2004 के अर्ध वर्ष, में 1.7 लाख करोड़ रुपए का था। इक्विटी स्पाट और व्युत्पाद बाजारों ने हाल के वर्षों में प्रमुख सुधार देखे और इन सुधारों से सुधरी हुई नकदी और सुदृढ़ता के परिणाम प्राप्त हुए हैं। एक बड़े व्यापार के मूल्य प्रभाव को मापते हुए प्रभाव लागत से बाजार की नकदी और गहराई का पता लगता है। शीर्ष के 50 स्टॉकों की प्रभाव लागत 2004 में इस स्तर तक गिर गई जो हाल ही में 2001 में अवलोकित स्थर का एक तिहाई थी।

1.38 प्रतिभूति बाजारों में प्रत्यक्ष घरेलू सहभागिता जो 2002 में अवरुद्ध हो गई थी, 2003 तथा 2004 में महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ हो कर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

में 6 मिलियन खातों के स्तर तक पहुंच गई। विविध सहभागिता इक्विटी बाजारों के लिए मजबूती का प्रमुख स्रोत है। एफ आई आई ने भी कुल बाजार बिक्री में अपना हिस्सा बढ़ाकर 5.8 प्रतिशत करके इक्विटी बाजार में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अद्यतन दो वर्षों में, शीर्ष के 50 स्टॉकों (निफ्टी) का सह संबंध यु. एस. एस एंड पी 500 सूचकांक की तुलना में 0.33 था। अगले 50 स्टॉकों (निफ्टी जूनियर) का सह संबंध मात्र 0.20 था। इन न्यून सहसंबंधों का निहितार्थ यह है कि भारतीय इक्विटियां वैश्विक पोर्टफोलियो के विविधीकरण हेतु एक साधन के रूप में काफी आकर्षक बनी हुई हैं।

#### (ख) उपभोग, बचत और निवेश

1.39 वर्ष 2002-03 में अवलोकित बचतों की दरों और निवेश में सुधार 2003-04 में पूरे वर्ष जारी रहा है। बचत दर जो स.घ.उ. के अनुपात के रूप में चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू बचत है, 2001-02 में 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 26.1 प्रतिशत हो गई। निवेश दर (स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण) में 22.6 प्रतिशत की तुलना में 24.8 प्रतिशत की सादृश वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 में बचतों और निवेश दरों में और सुधार हुए जो क्रमशः 28.1 प्रतिशत और 26.3 प्रतिशत थे। वर्ष 2003-04 में बचत दर अब तक दर्ज की गई बचत दरों में सर्वाधिक है और 2003-04 में निवेश दर 1996-97 से सर्वाधिक है (सारणी 1.3)।

1.40 वर्ष 2002-03 और 2003-04 हाल के वर्षों में देखी गई बचतों व निवेश दरों में गिरावट की प्रवृत्ति से विचलन दर्शाते हैं। बचत दर में सुधार मुख्यतया सार्वजनिक खर्च में कटौती और निजी बचतों में सुधार, घरेलू व निजी कारपोरेट दोनों में, के कारण हुआ है। घरेलू बचतों के तहत भौतिक आस्तियों की बचतों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जो 2001-02 में स.घ.उ. के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 और 2003-04, दोनों में स.घ.उ. का 13.0 प्रतिशत हो गयीं। इसके विपरीत, वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचत (फिर स.घ. उ. के अनुपात के रूप में) 2001-02 में 11.2 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 10.3 प्रतिशत होने के पश्चात 2003-04 में सुधारकर 11.4 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, अपेक्षतया उच्च बचत दर सभी तीनों क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन में सुधार के कारण हुई थी। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए खर्चों की प्रवृत्ति में प्रतिवर्तन था जब खर्च 2001-02 में स घ उ के 2.7 प्रतिशत से गिरकर 2002-03

सारणी 1.3 : बचत और निवेश								
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 (अ)	2003-04 (क्यू)
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)								
सकल घरेलू उत्पाद	23.2	23.1	21.5	24.2	23.5	23.4	26.1	28.1
क) सरकारी	1.7	1.3	-1.0	-1.0	-2.3	-2.7	-1.1	-0.3
ख) निजी	21.5	21.8	22.5	25.2	25.8	26.2	27.2	28.5
i) पारिवारिक	17.0	17.6	18.8	20.9	21.6	22.6	23.3	24.3
वित्तीय	10.4	9.6	10.4	10.6	10.4	11.2	10.3	11.4
वास्तविक	6.7	8.0	8.4	10.3	11.3	11.4	13.0	13.0
ii) निजी कॉरपोरेट	4.5	4.2	3.7	4.4	4.1	3.6	3.8	4.1
सकल घरेलू निवेश*	24.5	24.6	22.6	25.3	23.8	22.6	24.8	26.3
सरकारी	7.0	6.6	6.6	6.9	6.3	6.2	5.4	5.6
निजी	14.7	16.0	14.8	16.7	16.3	16.0	17.3	17.4
जीएफसीएफ	22.8	21.7	21.5	21.8	22.0	22.1	22.2	22.7
स्टॉक में परिवर्तन	-1.0	0.9	-0.1	1.9	0.6	0.1	0.4	0.3
बचत-निवेश में अंतर@	-1.3	-1.5	-1.1	-1.1	-0.4	0.8	1.3	1.8
सरकारी	-5.4	-5.3	-7.6	-8.0	-8.6	-8.9	-6.4	-5.9
निजी	6.8	5.8	7.7	8.5	9.4	10.1	9.9	11.0
टिप्पणी :	(i) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है।							
	(ii) आंकड़े पूर्णक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।							
* :	भूल-चूक के लिए समायोजित							
@ :	बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।							
जी.एफ.सी.एफ. :	सकल नियत पूंजी निर्माण							
अ :	अनन्तितम                      क्यू : त्वरित अनुमान							
स्रोत :	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन							

में 1.1 प्रतिशत और 2003-04 में और गिरकर स.घ.उ. का 0.3 प्रतिशत हो गई।

1.41 निवेश दर में सुधार महत्वपूर्ण रूप से निजी निवेश से हुआ है जो 2001-02 में 16.0 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 17.3 प्रतिशत तथा 2003-04 में और बढ़कर 17.4 हो गया। सार्वजनिक निवेश 2000-01 से निरंतर गिरने के पश्चात् 2002-03 में 5.4 प्रतिशत से सुधरकर 2003-04 में 5.6 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। यह 2002-03 में 5.8 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2003-04 में 16.8 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि निजी निवेश ने महत्वपूर्ण रूप से समग्र निवेश दर में परिवर्तन बनाए रखा और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का निष्पादन सुधरा है, निजी क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण की अभिवृद्धि में गिरावट हुई है जो 2002-03 में 17.1 प्रतिशत से 2003-04 में 13.1 प्रतिशत हो गई।

1.42 स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जी डी सी एफ) 2002-03 में 17.4 की अभिवृद्धि से अपेक्षाकृत

कम होकर 2003-04 में 13.8 प्रतिशत बढ़े हैं। दोनों वर्षों में अभिवृद्धि स.घ.उ. की तुलना में अपेक्षतया अधिक थी परन्तु स.घ.उ. अभिवृद्धि और जी डी सी एफ अभिवृद्धि में अंतर कम होने के कारण 1993-94 के बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में जी डी सी एफ में वृद्धि 2002-03 में 3.1 प्रतिशतांक की तुलना में 2003-04 में सिर्फ 1.3 प्रतिशतांक थी (सारणी 1.4)। यह सुधार मुख्यतया निजी क्षेत्र से हुआ है। वर्ष 2000-01 से अवलोकित सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निर्माण में निरंतर गिरावट 2003-04 में प्रतिवर्तित हो गई।

1.43 स.घ.उ. में निवेश का बढ़ता हुआ हिस्सा सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जी एफ सी ई) और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पी एफ सी ई) को मिलाकर बने अंतिम उपभोग व्यय के हिस्से में गिरावट में प्रतिबिंबित हुआ था जो 2002-03 में 76.2 प्रतिशत से 75.3 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. में अंतिम उपभोग व्यय के हिस्से में गिरावट जी एफ सी ई और पी एफ सी ई दोनों में तदनुसूची गिरावट द्वारा चालित थी। उपभोग व्यय में 0.3 प्रतिशतांक की मामूली

सारणी 1.4 : वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण							
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (अ)	2003-04 (क्यू)
(बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 1993-94 मूल्य)							
जी.डी.सी.एफ.*	25.9	24.6	27.8	26.3	24.3	27.4	28.7
सरकारी	6.5	6.6	7.0	6.2	6.0	5.2	5.3
निजी	17.3	16.7	19.0	18.8	17.9	19.8	19.9
निजी कापॉरिटे क्षेत्र	9.0	7.6	7.7	6.4	5.5	5.3	5.6
पारिवारिक क्षेत्र	8.3	9.1	11.3	12.4	12.4	14.5	14.3
जी.एफ.सी.एफ.	22.8	23.4	23.9	24.0	23.8	24.6	24.8
सरकारी	6.2	6.4	6.2	6.0	5.7	5.5	5.7
निजी	16.6	17.0	17.7	18.0	18.1	19.1	19.1
स्टॉक में परिवर्तन	0.9	-0.1	2.0	1.1	0.1	0.5	0.3
सरकारी	0.3	0.1	0.8	0.3	0.3	-0.2	-0.4
निजी	0.7	-0.3	1.2	0.8	-0.2	0.7	0.7
(वृद्धि दर प्रतिशत में)							
जी.डी.सी.एफ.*	7.7	0.7	20.8	-1.4	-2.9	17.4	13.8
सरकारी	-0.8	7.3	13.3	-7.2	1.4	-8.9	10.0
निजी	16.4	2.6	21.5	3.0	0.0	15.5	8.7
जी.एफ.सी.एफ.	2.1	8.7	9.3	4.1	4.3	7.7	9.7
सरकारी	-2.8	9.4	2.7	0.4	0.3	0.4	13.1
निजी	4.1	8.4	11.8	5.4	5.6	10.0	8.7
टिप्पणी : जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण; जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण; आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं। * : भूल-चूक के लिए समायोजित अ : अनन्तिम; क्यू : त्वरित अनुमान स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन							

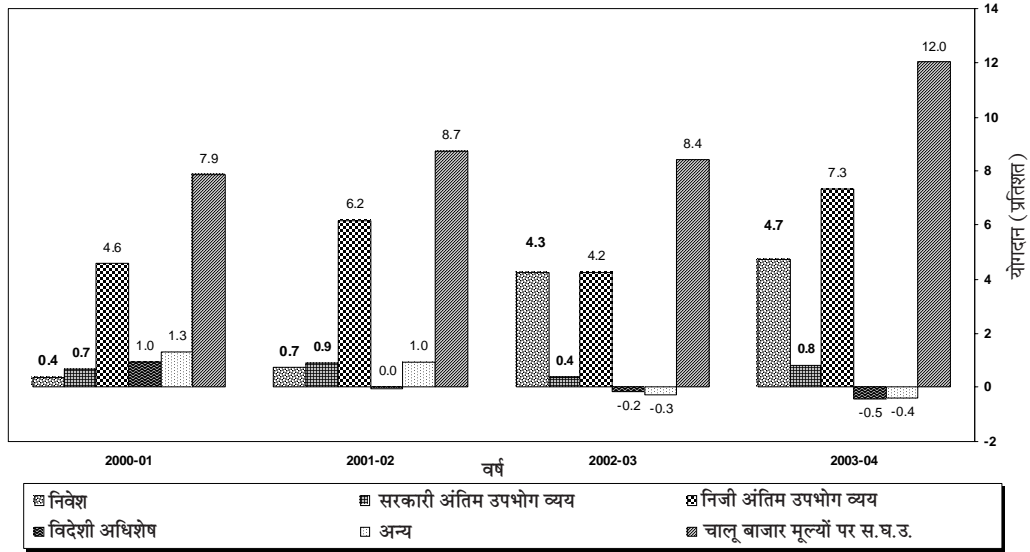
गिरावट के साथ पी एफ सी ई-स.घ.उ. अनुपात गिरकर 64.0 प्रतिशत पर आ गया। इसके अतिरिक्त पी एफ सी ई में जबकि खाद्य पदार्थों, मादक पेय पदार्थ तथा तंबाकू, किराया, ईंधन और विद्युत के हिस्से में गिरावट हुई थी, परिवहन व संचार के हिस्सों में सुधार हुआ था।

1.44 उपभोग व्यय खासकर पी एफ सी ई, स.घ.उ. की अभिवृद्धि में प्रमुख अंशदाता रहा है। स.घ.उ. की अभिवृद्धि में पी एफ सी ई का अंशदान 2002-03 में 50.4 में प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 60.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में जी एफ सी ई का अंशदान भी 4.3 प्रतिशत से सुधरकर

सारणी 1.5 : सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन										
संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1993-94 मूल्यों पर)				
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03P	2003-04Q	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03अ	2003-04क्यू
कुल अंतिम उपभोग व्यय	12.5	6.7	9.1	5.9	10.7	7.1	2.4	5.3	2.0	7.5
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	17.3	5.2	7.2	2.9	7.1	13.2	0.5	3.1	-2.4	3.7
निजी अंतिम उपभोग व्यय	11.6	7.0	9.5	6.5	11.4	6.0	2.8	5.8	2.8	8.2
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें से	24.8	1.5	3.1	18.8	19.1	20.8	-1.4	-2.9	17.4	13.8
सकल नियत पूंजी निर्माण	12.7	8.8	9.2	9.3	14.5	9.3	4.1	4.3	7.7	9.7
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	16.6	22.1	4.5	22.3	14.7	—	—	—	—	—
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	18.2	12.0	4.5	22.2	16.7	—	—	—	—	—
बाजार मूल्यों पर स.घ.उ.	11.2	7.9	8.7	8.4	12.0	7.1	3.9	5.1	4.1	8.6
क्यू : त्वरित अनुमान। अ : अनन्तिम स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।										

चित्र 1.2

## चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि में योगदान



6.9 प्रतिशत हो गया। अभिवृद्धि में निवेश का अंशदान किसी सुसंगत पद्धति का अनुकरण नहीं कर रहा है। अभिवृद्धि में इसका बिंदु अंशदान 2001-02 में 8.4 प्रतिशत से 2002-03 में 50.6 प्रतिशत के बीच रहा है। वर्ष 2003-04 में इसने स.घ.उ. अभिवृद्धि में 39.3 प्रतिशत का योगदान किया है। वैदेशिक क्षेत्र का अंशदान 2002-03 में -2.2 प्रतिशत और 2003-04 में -3.8 प्रतिशत पर ऋणात्मक बना रहा है। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में स.घ.उ. अभिवृद्धि में पी एफ सी ई, जी एफ सी ई, निवेश और वैदेशिक क्षेत्र का औसत अंशदान क्रमशः 61.4 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत 30.6 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत था।

## (ग) उत्पादन

1.45 कुल खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन मोटे अनाजों व दालों के उत्पादन में कमी के साथ पिछले वर्ष 212 मिलियन टन से गिर 2004-05 में 206.4 मिलियन टन होने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में चावल और गेहूँ का उत्पादन वास्तव में अपेक्षातया अधिक होना अनुमानित है। पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के साथ फलों व सब्जियों, मसालों, पुष्प कृषि और नारियल समाहित बागवानी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र से स.घ.उ. के 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया है और इन उप-क्षेत्रों में चालू वर्ष में भी बेहतर उत्पादन दिखाई देता है। वर्ष 2004-05 में कपास की जबरदस्त फसल जिसमें

पिछले वर्ष से लगभग 24 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए शुभ है। चालू वर्ष में महाराष्ट्र के कुछ भागों में कम वर्षा से गन्ने के उत्पादन में निरंतर तीसरे वर्ष अधोगामी प्रवृत्ति बने रहने की संभावना है।

1.46 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ने 2004-05 की पहली तिमाहियों में 8.4 प्रतिशत की प्रभावशाली अभिवृद्धि दर्ज की है जो 1995-96 के बाद से सर्वाधिक है। पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में उत्पादन के स्रोतों के साथ-साथ प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार सभी स्थूल समूहों में सुधार हुआ है। यह सुधार विशेषकर विनिर्माणी में व पूंजीगत सामान तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में स्पष्ट है। व्यापकाधारित सुधार का निहितार्थ निवेश और उपभोग मांग दोनों में सुधार भी है।

1.47 अप्रैल 2004 में आई आई पी में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ, यह वर्ष एक उत्प्लावक संकेत से आरंभ हुआ। मई 2004 में 6.8 प्रतिशत पर वार्षिक वृद्धि में धीमापन अस्थायी सिद्ध हुआ और प्रत्येक अनुवर्ती महीने में वृद्धि त्वरित होकर अक्टूबर में 9.8 प्रतिशत के चरम-स्तर पर परिलक्षित हुई। आई आई पी वृद्धि जो नवम्बर 2004 में 7.7 प्रतिशत हो गई थी, में गिरावट दिसंबर में प्रतिवर्तित हो गई, जब वृद्धि पुनः 7.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। औद्योगिक मोर्चे पर सबसे अधिक सकारात्मक विकास विनिर्माण क्षेत्र में

हुआ। वर्ष 2004 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि अप्रैल में 8.8 प्रतिशत से गिरकर मई में 7.5 प्रतिशत होने के पश्चात्, प्रत्येक माह निरंतर त्वरित होते हुए सितंबर तथा अक्टूबर में द्वि-अंकीय स्तरों पर पहुंच गई। विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं ने उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए मई को छोड़कर चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में से प्रत्येक में द्वि-अंकीय वर्षानुवर्ष वृद्धि दरें दर्ज करके गतिशीलता प्रदर्शित करना जारी रखा। सितंबर 2004 में, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत पर संतोषजनक रूप से उच्च थीं।

1.48 वर्गीकरण के द्वि-अंकीय स्तर पर सत्रह उद्योग समूहों में से अप्रैल-दिसंबर 2004 में, चार ने द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की; चार में 5 से 10 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई; और छः में वृद्धि 0 से 5 प्रतिशत के बीच थी। तीन प्रमुख समूहों नामतः परिवहन उपस्कर के अलावा मशीनरी और उपस्कर, कहीं अन्यत्र शामिल न किए गए अन्य विनिर्माण उद्योग और आधारिक रसायन और रसायन उत्पादों (पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर) जिनका विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 32.9 प्रतिशत का और कुल आईआईपी में 26.1 प्रतिशत का सकल भारांश है, ने क्रमशः 21.9 प्रतिशत 19.4 प्रतिशत और 15.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दरें दर्ज कीं। खाद्य उत्पाद, जूट और अन्य सूती-भिन्न वनस्पति रेशे और लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर तथा फिक्सचर्स, जिनका विनिर्माण क्षेत्र में 15.6 प्रतिशत और आई आई पी में 12.3 प्रतिशत का कुल भारांश है, चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले केवल मात्र क्षेत्र थे।

1.49 चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में भारतीय वस्त्र उद्योग से उसके 1 जनवरी, 2005 से वस्त्रों में कोटा-मुक्त विश्व व्यापार व्यवस्था में चुनौतियों का सामना करने में तैयारी के संबंध में, कुछ उत्साहवर्धक संकेत प्राप्त हुए हैं। वस्त्र उत्पादों (जिनमें पहनने वाले परिधान शामिल हैं) के लिए आई आई पी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 2.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2004 में 14.8 प्रतिशत बढ़ा है। सूती वस्त्रों के वृद्धि निष्पादन में भी 14 प्रतिशतांक का और बड़ा सुधार हुआ, जो एक वर्ष पूर्व की 5.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में 8.3 प्रतिशत हो गए। चालू वर्ष के लिए निवेश आशय वस्त्र क्षेत्र में संवृद्धि प्रक्रिया का सुदृढीकरण सुझाते हैं।

सामान्य समीक्षा

website:<http://indiabudget.nic.in>

1.50 ऑटोमोबाईल और ऑटो-संघटक उद्योग ने वर्ष 2003-04 में अच्छा निष्पादन किया। वर्ष 2003-04 में ऑटो-संघटकों के कुल बिक्री कारोबार में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि थी। चालू वर्ष में संतोषजनक रूझान जारी रहते प्रतीत होते हैं, उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाईल उद्योग में कुल वाहनों का उत्पादन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 5.2 मिलियन से बढ़कर चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में 6.2 मिलियन हो गया है। वर्ष 2003-04 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (आई टी) के उत्पादन का 18.2 प्रतिशत बढ़कर 1,14,650 करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है। अप्रैल-दिसंबर, 2004 के दौरान, इस्पात का उत्पादन 28.3 मिलियन टन बढ़ गया और इसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर, 2004 के दौरान, 96.3 मिलियन टन पर सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के उत्पादन से 6.81 प्रतिशत उच्चतर था।

1.51 छः केन्द्रीय उद्योगों ने (बिजली, कोयला, तैयार इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद), जिनके आई आई पी में 26.68 प्रतिशत का भारांश रखते हुए, शेष अर्थव्यवस्था के साथ महत्वपूर्ण अग्रवर्ती सम्पर्क थे, ने वर्ष 2003 में अप्रैल-दिसम्बर के दौरान 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2004 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 5.4 प्रतिशत की निम्नतर औसत वृद्धि दर्ज की। यह गिरावट तैयार इस्पात की संवृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण थी। अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में से, रेलवे पर माल यातायात (7.7 प्रतिशत), मुख्य समुद्री पत्तनों पर कार्गो सेवाएं (11.1 प्रतिशत), और वायुपत्तन (18.3 प्रतिशत) और हवाई यात्रा यातायात (21.8 प्रतिशत) ने वर्ष 2003 में अप्रैल-दिसंबर की तुलना में 2004 की इसी अवधि में उच्चतर संवृद्धि दरें परिलक्षित की।

#### (घ) रोजगार और गरीबी

1.52 योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा संचालित घरेलू उपभोक्ता व्यय, श्रमिक बल और रोजगार पर संचालित विस्तृत पंचवर्षीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी और बेरोजगारी के विस्तार का आकलन करता है। पिछले ऐसे सर्वेक्षण के वर्ष 1999-2000 के दौरान केवल 55वें दौर में संचालित होने से, वर्ष 1999-2000 के बाद गरीबी और बेरोजगारी के कोई शासकीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। ये अंतिम शासकीय अनुमान पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में सूचित किए गए थे। यद्यपि, सर्वेक्षण के तदनंतर लघु-वार्षिक दौर ये

सुझाते हैं कि गरीबी कम हुई है और रोजगार बढ़ा है, ये असंख्य प्रतिदर्श और प्रतिदर्श-भिन्न गलतियों के अध्यधीन हैं।

1.53 मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) आय, स्वास्थ्य और शिक्षा के तीन आवश्यक आयामों को शामिल करता है। हालांकि एच डी आई और गरीबी के बीच एक के प्रति एक कोई विपरीत सादृशता नहीं है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) द्वारा एच डी आई में अद्यतन मानव विकास रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित एचडीआई वर्ष 1995 और 2002 के बीच गरीबों में संभावित गिरावट के समर्थन में कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। भारत का एच डी आई वर्ष 1995 में 0.548 से सुधरकर वर्ष 2000 में 0.579 हो गया तथा वर्ष 2002 में और सुधरकर 0.595 हो गया।

1.54 सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) विकास प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता और उससे उससे पूरी तरह लाभान्वित होने में उन्हें समर्थ बनाने हेतु सामाजिक क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता देता है। वर्ष 2004-05 में इस संबंध में शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रमों में ये शामिल हैं- 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आजीविका संरक्षण में संवृद्धि की व्यवस्था हेतु दिनांक 21 दिसंबर, 2004 को संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004 की पुरःस्थापना, आयोजना कार्यक्रमों जैसे काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेय जल और सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सकल बजटीय समर्थन (जी बी एस) की व्यवस्था, अन्त्योदय अन्न योजना के विस्तार को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ परिवारों को शामिल करना, केन्द्रीय करों और शुल्कों पर 2 प्रतिशत के उपकर के अधिरोपण द्वारा सार्वभौम शिक्षा की सुविधाओं में सुधार, अगले 5 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उन्नयन और गरीबों के लिए एक नई सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना और एक विशिष्ट समूह बीमा योजना की पुरःस्थापना।

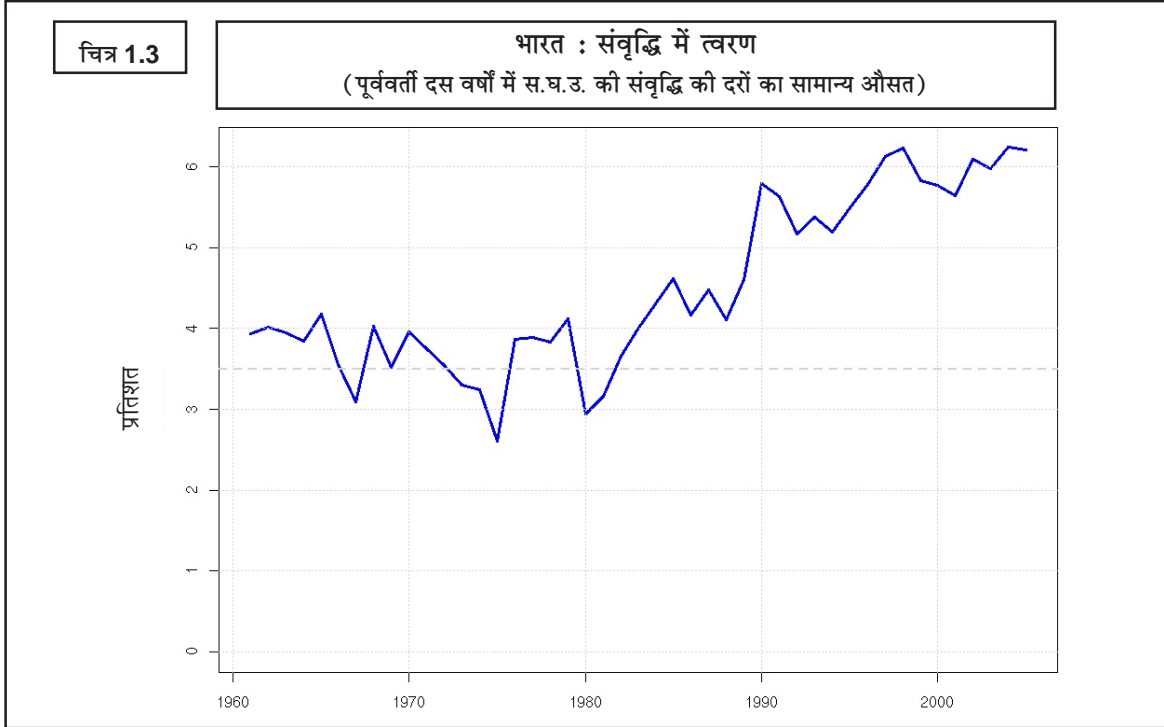
### मुद्दे और प्राथमिकताएं

1.55 पिछली समीक्षा ने संवृद्धि प्रक्रिया के सुदृढीकरण के लिए निवेश माहौल का पोषण करने की आवश्यकता को इंगित किया था। दोनों मोर्चों पर सकारात्मक विकास के कुछ उत्साहवर्धक संकेत हैं।

1.56 प्रथम, निवेश में तेजी आई है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण, अर्थात् निवेश दर, वर्ष 2001-02 से 3.7 प्रतिशतांक बढ़कर 2003-04 में 26.3 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 1996-97 के बाद से उच्चतम है। प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक बाजार में वर्धित गतिविधि है, जब कैलेंडर वर्ष 2004 में निर्गम की समग्र प्रमात्रा में पांच गुणा से अधिक वृद्धि हुई। मध्य-फरवरी, 2005 में स्टॉक बाजार सूचकांक अब तक के उच्चतम शीर्ष पर थे।

1.57 दूसरा, वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिवृद्धि निष्पादन अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रूझान दर में संभावित अनिवर्तन निर्दिष्ट करते हैं जो 6 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष (चित्र 1.3) हो गई। चालू वर्ष के घटनाक्रम इसके समर्थन का साक्ष्य है। भुगतान संतुलन का चालू खाता घाटे में परिवर्तित हो गया है, जो बचतों की तुलना में निवेश का आधिक्य दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवृद्धि वर्ष के प्रारंभ तथा आरम्भिक भाग में किए गए लगभग सभी परिकलनों को पार कर चुकी है। 'आयातित' किस्म की मुद्रास्फीति में एक प्रारंभिक तेजी देखी गई, जो अल्प दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा उत्पन्न स्फीतिकारी प्रत्याशाओं के कारण बढ़ता हो गई। मुद्रास्फीति दर में तीव्र गिरावट उत्पादक क्षेत्रों की विस्तृत विविधता से लचीली आपूर्ति अनुक्रिया की क्षमता इंगित करती है। जहां वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दो वर्षों में अर्थव्यवस्था के निष्पादन की व्यवसाय-चक्र किस्म की व्याख्या भी तर्कसंगत है, सितंबर, 2003 से पूंजीगत वस्तुओं (अक्टूबर, 2003 और नवंबर, 2004 को छोड़कर) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (मई, 2004 को छोड़कर) में हाल ही में अवलोकित वर्षानुवर्ष निरंतर द्वि-अंकीय वृद्धि दरों के साथ-साथ बचतों एवं निवेश में वृद्धि को देखते हुए, एक संवृद्धि के रूझान की अपेक्षा की जा सकती है।

1.58 तथापि, एन सी एम पी के "कि अर्थव्यवस्था एक दशक तक सतत् तरीके से कम से कम 7-8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़े और इस प्रकार से बढ़े कि रोजगार उत्पन्न हो ताकि हर परिवार एक सुरक्षित और व्यवहार्य आजीविका के प्रति आश्वासित हो" सुनिश्चित करने के अधिदेश की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रयासों की आवश्यकता है। अपने "दसवीं योजना के मध्य-आवधिक मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण" में योजना आयोग ने यह निर्दिष्ट किया था कि एन सी एम पी के संवृद्धि उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्योग में 10 प्रतिशत



से अधिक की वृद्धि अत्यावश्यक है। यह संदिग्ध है कि केवल वृद्धिकारी-पूंजी उत्पादन अनुपात में कटौती करके निवेश के वर्तमान स्तरों पर लक्षित उच्च संवृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। पिछले दो वर्षों में वृद्धि के बावजूद, निवेश दर चीन और पूर्व एशिया से न केवल बहुत नीचे है बल्कि यह दसवीं योजना में अनुमानित दर से भी निम्नतर है।

1.59 कुल जनसंख्या में कार्यशील उम्र की जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि और बढ़ती हुई आयों के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों ने बचत दर पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस यथार्थ रूझान के कुछ वर्षों तक जारी रहने की आशा है। इसके साथ ही, बचत दर में हाल ही के सुधार का एक भाग लोक खर्च में गिरावट के कारण है। एफ आर बी एम अधिनियम ने लोक वित्त साधनों को सुधारने में, और न केवल सरकार द्वारा निवेशित संसाधनों के अग्रक्रयों में बल्कि संवर्धित पूंजी व्यय के लिए राजकोषीय स्थान बनाने के लिए राजस्व व्ययों में भी कटौती की ओर ध्यान संकेन्द्रित किया है। एफ आर बी एम नियमावली की अधिसूचना के साथ, केन्द्र के राजस्व घाटे में योजनाबद्ध कटौती न केवल प्रत्यक्ष रूप से बचत और निवेश के संवर्धन में सहायक होगी बल्कि राजकोषीय अवस्थिति की वर्धित विश्वसनीयता के माध्यम से, ब्याज दर और इस प्रकार निवेश मोर्चे पर तत्काल अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगी। बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है

कि प्रत्येक राज्य को 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटा कम करके राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर लाने की व्यवस्था करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करना चाहिए। इस अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा राजकोषीय सुधारों के साथ राज्यों की केंद्रीय ऋण राहत के साथ सम्बंधन को केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राज्य स्तर पर राजकोषीय सुदृढीकरण को आगे बढ़ाया जा सके।

1.60 राजकोषीय सुधारों की एक चुनौती उपयुक्त कर सुधारों से राजकोषीय सुदृढीकरण की आवश्यकता को पूरा करना होगा। अप्रत्यक्ष कर न केवल संसाधन आवंटन की क्षमता को वरन निवेश के माहौल को भी प्रभावित करते हैं। चूंकि केन्द्र और राज्य सरकारों के कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता है, अतः विरोधाभासी उद्देश्यों में सन्तुलन लाने के लिए इन करों के सुधार को सावधानीपूर्वक अंशांकित करने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल 2005 से राज्य स्तर पर वैट लागू करने की घोषणा वर्तमान बिक्री कर व्यवस्था के सोपानी प्रभाव को दूर करने में दूरगामी सिद्ध होगी। अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर कर हटाने और समूचे देश को एक साझा बाजार के रूप में एकीकृत करने तथा वैट दरों के उचित अंशांकन सहित सभी राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों का वैट के रूप में एकीकरण करने से दक्षता और राजस्व संग्रहण के

दोनों उद्देश्यों में तालमेल बिठाया जा सकता है। सीमा शुल्क दरों को आसियान स्तर से जोड़ने की दिशा में प्रगति, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी और निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहित किया प्रतीत होता है, जारी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार के राजस्व में इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि, यदि कोई हो, को भरपाई अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व और छूटों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर की जा सकती है। केन्द्र और राज्य दोनों को अपने कर प्रशासनों में एक ऐसी पूर्वाग्रह-रहित और असुविधाहित व्यवस्था को अपना कर सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसमें ईमानदार कर दाता के लिए कम अनुपालन लागत हो और कर वंचक के लिए भारी जोखिम हो। ऐसा नवीन तरीके अपनाकर किया जा सकता है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रयोग न सिर्फ सूचना संग्रहण, डाटा संचय और विश्लेषण के लिए ही किया जाए बल्कि स्रोत पर कर-राजस्व के स्वतः संग्रहण हेतु भी किया जाए।

1.61 एफ आर बी एम अधिनियम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के प्रभावपूर्ण माध्यम से राजकोषीय सुदृढीकरण के प्रश्न से इतर निवेश में वृद्धि के लिए पांच ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पहला कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में निवेश का मुद्दा है जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स.घ.उ. का केवल 21 प्रतिशत उत्पादन होता है, लेकिन यह लगभग 57 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करता है। हालांकि कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन का जैसे फल और सब्जियां, फलों की खेती, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों की ओर कुछ विविधीकरण हुआ है, फिर भी ऐसे विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। अपर्याप्त भण्डारण और परिवहन सुविधाओं तथा पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी के चलते पैदावार में भारी नुकसान होता है। इन फसल-पश्च सुविधाओं में और अधिक सरकारी और निजी निवेश की आवश्यकता न केवल कृषि में मूल्यवर्धन करने के लिए वरन कृषि और ग्रामीण औद्योगिकीकरण के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिए भी है। इसके ग्रामीण क्षेत्र में जहां देश की गरीब आबादी का लगभग 75 प्रतिशत बसता है, बेरोजगारी और गरीबी पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

1.62 भारतीय कृषि को, अधिक क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत लाकर और बेहतर जल प्रबन्धन के जरिए सदियों पुरानी मानसून पर निर्भरता से आगे ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसकी सर्वाधिक

निवेश वाले एक क्षेत्र के रूप में सही पहचान की गई है। इसी संदर्भ में कृषि को दी जाने वाली राजकोषीय सहायता का उपर्युक्त ढांचा महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय सुदृढीकरण की बाध्यताओं के चलते, चुनाव एक तरफ फसलों, उर्वरक, सिंचाई और विद्युत के मूल्य समर्थन के लिए सब्सिडी और दूसरी तरफ सिंचाई, सड़कों, विद्युतीकरण, कृषि प्रसार तथा अनुसंधान के लिए सहायक बुनियादी ढांचे में उच्चतर सार्वजनिक निवेश के बीच है। इन निवेशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का न केवल अनाजों वरन कृषि से भी आगे जाकर विविधीकरण सम्भव है। इन निवेशों के साथ-साथ कृषि व्यापार में स्थिर नीति से हाल के वर्षों में देखी गई कृषि निर्यात में तेजी को प्रोत्साहन मिलने के आसार हैं।

1.63 दूसरा मुद्दा क्रियाविधियों के सरलीकरण और प्रवेश-विकास अवरोधों में ढील देने से सम्बन्धित है। वह सहजता जिससे कम्पनियां व्यापारिक गतिविधियों में प्रवेश कर सकती हैं तथा उससे निकल सकती हैं, निवेश माहौल का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कारोबार शुरू करने के लिए, बड़ी संख्या में केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मंजूरियां लेनी होती हैं। यह प्रणाली विलम्ब का कारण बनती है और इससे भ्रष्टाचार के मौके पनपते हैं। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कारोबार पर भारी विनियामक बोझ के कारण, भारत अभी भी व्यापार करने की सहजता के संबंध में तुलनात्मक राष्ट्रों की सूची में बहुत नीचे है। चीन में, कोई कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने, अथवा दिवालियापन की प्रक्रिया पूरी करने में लिये जाने वाले औसत समय भारत की अपेक्षा काफी कम है। भारतीय श्रम कानून, विशेषकर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अध्याय V ख चीन, ब्राजील या मैक्सिको के श्रम कानूनों की अपेक्षा कम छूट प्रदान करता है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण के प्रत्याशित परिणाम नहीं मिले हैं और इससे कुछ अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे निटवीयर, जिसमें वृद्धि की बहुत सम्भावना है, में निवेश बाधित हुआ है। ऐसे आरक्षणों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसी सभी मदों का अब मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। कोटा-प्रणाली के बाद के दौर में अपार सम्भावित लाभों का फायदा उठाने के लिए वस्त्रोद्योग क्षेत्र की सफलता निर्धारित करने में प्रवेश-निकास अवरोधों को दूर करना निर्णायक होगा। हाल ही में गठित निवेश आयोग, जिसे उद्योग समूह/घरानों तथा विदेशों में बड़ी कम्पनियों के साथ विचार-विनिमय करने, निवेश हासिल करने तथा क्रियाविधियों व



नीतियों के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए भी अधिदेश प्राप्त है, से मदद मिलनी चाहिए। इसी प्रकार, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद भी विनिर्माण को विस्तृत संभावना से लाभ उठाने के लिए जरूरी नीतियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान आकृष्ट करने में मदद करेगी।

1.64 तीसरा मुद्दा वित्त का है। आधारभूत ढांचा, उद्योग (आवास सहित) तथा सेवाओं में आरम्भिक निवेश उछाल के बेहतर परिणाम केवल तभी मिलेंगे जब अपार संसाधन प्रवाहों को कम लागत पर सफलतापूर्वक मध्यवर्तियों द्वारा निर्दिष्ट उपयोग के लिए पहुंचाया जाए। यह सूचना को सही ढंग से व्यवहार में लाने और घरेलू तथा विदेशी बचतों को विशिष्ट फर्मों और क्षेत्रों द्वारा इष्टतम निवेश के रूप में परिवर्तित करने पर निर्भर करेगा।

1.65 कृषकों और उद्यमियों की कार्यक्षम दरों पर और उनकी ऋण-योग्य परियोजनाओं के लिए सभी परिपक्वताओं के लिए वित्त तक पहुंच होनी चाहिए। हाल के वर्षों में, उदाहरण के लिए, ऋण ब्यूरो के जरिए गतिशील ऋण सूचना प्रवाह स्थापित करके और ऋण के प्रवर्तन में सुधार लाकर ऋण बाजारों में सुधार लाने में कुछ प्रगति हुई है। 1990 के दशक के आरम्भ से टी+2 चल निपटान, स्क्रीन-आधारित अनाम आर्डर-मैचिंग, अभौतिकीकरण तथा बहुल एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा से इक्विटी बाजार में नाटकीय सुधारों ने निवेशक आधार को विविधीकृत कर दिया प्रतीत होता है। फिर भी ऋण और इक्विटी बाजारों, दोनों में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कीमत-लागत अंतर को कम करने, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने, ऋण-संस्कृति में सुधार लाने तथा कारोबार आरम्भ करने वालों तथा लघु इकाइयों के बीच भावी सफल उद्यमियों की पहचान करने के लिए बेहतर ऋण-मूल्यांकन कौशल के लिए बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा और दक्षता की आवश्यकता है। इक्विटी बाजारों की तेजी को एक स्क्रीन-आधारित अनाम आर्डर-मैचिंग तथा वैकल्पिक कारोबारी मंचों में प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर होकर ऋण-बाजार की ओर भी विस्तार करने की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण मानदण्डों के अधीन, न केवल उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वरन लघु बचतकर्ताओं को भी ऐसे बेहतर प्रतिफल प्रदान करने, जिनके इन बाजारों से मध्यावधि में मिलने की सम्भावना है, के लिए इक्विटी और दीर्घावधिक ऋण बाजारों में पेंशन निधियों और संविदात्मक बचत योजनाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य समीक्षा

website:<http://indiabudget.nic.in>

1.66 चौथा मुद्दा आधारभूत ढांचा है। बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता आर्थिक विकास को बाधित करती है, विशेषकर पिछड़े राज्यों में और कृषि क्षेत्र में। उदाहरण के लिए यदि अच्छी सड़कें नहीं हैं और शीतागार नहीं हैं तो फल व सब्जियां घरों की रसोई में पहुंचने से पूर्व ही सड़-गल जाएंगी। और शीतागार काम नहीं करेंगे, यदि विश्वसनीय और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं है। इसी प्रकार भले ही कोई विश्व स्तर का आकर्षक पर्यटन स्थल हो, यदि परिवहन के तीव्र साधन नहीं हैं और इसके इर्द-गिर्द शहरी आधारभूत ढांचा नहीं है तो यह बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में नाकाम रहेगा। आधारभूत ढांचा सेवाओं के सीधे तौर पर सरकारी निर्माण से तकनीकी दक्षता, निवेश की पर्याप्त मात्रा, प्रयोक्ता प्रभारों के उचित प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धी बाजार ढांचे के सम्बन्ध में कठिनाइयां आती हैं। इस प्रकार सीधे निर्माण से, उदाहरणार्थ, बुनियादी ढांचा जोखिम में पड़ सकता है जैसे सड़क निर्माण और रख-रखाव को गलत प्रयोक्ता प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जा सकता है और राजनीतिक दखल-न्दाजियां और बजटीय अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। निजी भागीदारी भी परियोजना तैयार करने के स्तर से लेकर, सरकारी क्षेत्र के लिए जोखिम की समस्या को कम करती है। साथ ही एक अनियमित बाजार में पूर्ण रूप से निजी भागीदारी पर निर्भरता से अच्छे परिणाम मिलने की सम्भावना नहीं है। आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी खर्च में कमी की मुख्यतया विनियामक माहौल में कठिनाइयों के कारण निजी क्षेत्र द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। अतः आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निजी-सरकारी भागीदारी को समर्थ बनाने वाला एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा खोजने की आवश्यकता है।

1.67 न्यूनतम सब्सिडी बोली प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम राशि का भाव देने वाला सेवा प्रदायक सब्सिडी भुगतानों का पात्र बनता है। पात्रता कार्यानिष्पादन के एक विनिर्दिष्ट स्तर अथवा सेवा प्रावधान अनिवार्यता को पूरा करने के अधीन है। यह वाणिज्यिक रूप से अक्षम, छितरी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन जैसी सुविधाओं जिनके लिए केवल प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से पूर्ण लागत वसूली व्यवहार्य नहीं है, में गरीब उपभोक्ताओं को बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करने हेतु एक उदीयमान रणनीति है। कई देशों ने इस नीति को विविध क्षेत्रों जैसे दूरसंचार (चिली, कोलम्बिया, पेरू और दक्षिण अफ्रीका), विद्युत (अर्जेन्टीना और चिली), सड़क पुनर्निर्माण और रख-रखाव (अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, चिली और यूके) तथा नागर विमानन (आस्ट्रेलिया और यू एस) में नियोजित किया है।

1.68 अनेक क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, सड़क, पत्तन और नागर विमानन जैसे क्षेत्रों में की गई अनेक पहलों के परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय विद्युत नीति में मुख्यतया अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने और 2012 तक पूरी तरह बिजली की मांग पूरा करने की परिकल्पना की गई है। दूरसंचार क्षेत्र के ढांचे और संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं जिसमें मोबाइल टेलीफोनों की संख्या कुल फोनों का 50 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की भागीदारी कुल फोनों के 44 प्रतिशत तक जा पहुंची है। ब्राडबैंड दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार भी आर्थिक वृद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। सड़कों के क्षेत्र में ध्यान निर्माण से हटाकर कॉरीडोर प्रबन्धन और सड़क सुरक्षा की ओर केन्द्रित करने की आवश्यकता है। पत्तनों में अन्तः-पत्तन और पत्तनों के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक पर्याप्त नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। रेल और सड़क के माध्यम से पत्तन संयोजकता का प्रावधान और कार्यनिष्पादन मानदण्डों और मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय बैचमार्किंग पत्तन क्षेत्र की वृद्धि को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। नागर विमानन क्षेत्र में, एयरलाइन उद्योग में विनियमन और प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने और बेहतर विमानपत्तनों का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक मूल्यों में देखी गई अस्थिरता और कच्चे तेल के लिए देश की आयात निर्भरता के चलते, सीमा-पार गैस पाइपलाइनों के आधारभूत ढांचे का विस्तार करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है।

1.69 पांचवा मुद्दा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) और विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में उच्चतर विदेशी निवेश की आवश्यकता है। यह निवेश प्रौद्योगिकी फैलाव को बढ़ावा देता है, मानव पूंजी निर्माण में सहायता करता है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एकीकरण और विशेषकर निर्यातों में योगदान करता है, एक अधिक प्रतिस्पर्धी व्यापार वातावरण तैयार करने में मदद करता है उद्यम विकास को बढ़ाता है, कुल उपादान उत्पादकता और व्यापक रूप में संसाधन प्रयोग की दक्षता को बढ़ाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक वैश्विक एकीकरण के परिणामस्वरूप कई घरेलू उद्योगों का विश्व उत्पादन श्रृंखलाओं में सफलतापूर्वक आत्मसातीकरण हुआ है। ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। विदेशी निवेश के प्रवेश में इन उद्योगों को प्रौद्योगिकीय उन्नयन और उच्चतर मूल्य वर्धन प्राप्त करने में सहायता की है।

1.70 जहां व्यापार उदारीकरण, अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरूआत तथा उदार विदेशी निवेश सम्बन्धी नीतियों से भारतीय विनिर्माण के कई क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी निकायों में परिवर्तित करने में मदद मिली है, वहीं कोयला खनन, बीमा, अचल सम्पदा और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में अधिकतम सीमा के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की प्रबल आवश्यकता है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश न केवल अधिकांशतः असंगठित घरेलू खुदरा बाजार क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से को संगठित कर सकता है, वरन भारतीय बाजार में प्रतिष्ठित विश्व ब्रांडों को भी आमन्त्रित कर सकता है, जिससे भारतीय उत्पादनों के स्रोतण और विपणन के लिए बेहतर आऊटलेट पैदा हो सकते हैं। संगठित खुदरा फार्मेट उत्पादों की गुणवत्ता का उन्नयन करने, फार्म से बाजार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित करने तथा अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजन करने में भी सहायक होंगे।

1.71 विकास में तेजी लाना आवश्यक है, परन्तु यह अर्थव्यवस्था में गरीबों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से लोगों को अधिकारिता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में परिकल्पित बेरोजगारी पर सीधे हमले को 21 दिसम्बर 2004 को संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004 के माध्यम से कार्यरूप दिया गया है। इस विधेयक में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करके ग्रामीण इलाकों में गरीबों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का उपबन्ध किया गया है। केन्द्र और राज्यों में विभिन्न कार्यों व कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए रोजगार गारंटी परिषदों की स्थापना की जानी है। इन योजनाओं की सफलता परिदाय व्यवस्था की दक्षता पर निर्भर करेगी। प्रशासनिक मशीनरी को उपयुक्त रूप से पुनर्संरचित करने और परिणामों की मानीटरिंग के लिए तन्त्रों को अमल में लाने की आवश्यकता है। एक सशक्त ग्रामीण अवसंरचना, विशेषतया पिछड़े जिलों में, का निर्माण करने के लिए इस अवसर का पूर्णतया प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन बड़ी हुई सरकारी जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त परिव्यय को सब्सिडी व्यवस्था के यौक्तिकीकरण से पूरा किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक परिचर्चा पत्र 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में रखा गया था। विभिन्न गरीबी उन्मूलन-कार्यक्रमों का एकीकरण इन कार्यक्रमों से धन के मूल्य में वृद्धि भी कर सकता है।

1.72 हाल के वर्षों में देखी गई वृहत आर्थिक स्थिरता को निरन्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। निवेश, गरीबों के संरक्षण और विकास को आगे ले जाने के लिए इस स्थिरता के फायदे सुविदित हैं। सुधार-पश्च अवधि में वृद्धि ने पूर्ववर्ती दशकों की आर्थिक मन्दियों, जब अर्थव्यवस्था को भुगतान सन्तुलन की समस्याओं से जूझना पड़ा था, से उबारा है। अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई बाह्य शक्ति को मजबूत करने और संस्थाओं व बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान निर्यात की गति में और तेजी

लाएगा। भारत में अब तक मांग पक्ष से विकास अधिकांशतः निजी अंतिम खपत से उत्प्रेरित रहा है और चीन और पूर्वी एशिया के विपरीत निवेश और निर्यात गौण भूमिका निभाते रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास को गति प्रदान करने के लिए निवेश और निर्यात में हाल की तेजी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश के माहौल में सुधार लाने और बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने के लिए सुधारों को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है।